RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शुक्रवार 06 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 163 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र के अस्पतालों में मौतों पर
एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईः महाराष्ट्र के तीन जिलों के अस्पतालों में मौतों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने सभी कलेक्टरों को अपने जिलों के सरकारी अस्पतालों का दौरा करने और तुरंत स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कलेक्टरों को राज्यभर के सभी सरकारी, नागरिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों का दौरा करने और वहां की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। शिंदे ने कलेक्टरों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी अस्पतालों का दैनिक/नियमित आधार पर दौरा करने और वहां की स्थिति की निगरानी करने का भी निर्देश दिया, हालांकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी और अन्य दल सरकार पर हमलावर हैं।

महाराष्ट्र में इस हफ्ते नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर के सरकारी अस्पतालों में और अगस्त की शुरूआत में उनके गृहनगर ठाणे के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत से लोगों में आक्रोश भड़क उठा था। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त सीएस

- सभी कलेक्टर से मांगी यह रिपोर्ट
- महाराष्ट्र के अस्पतालों में मौतों पर सीएम एकनाथ शिंदे की वर्चुअल मीटिंग
- मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी कलेक्टर को दौरा करने का कहा
- सीएम ने सभी कलेक्टर से दौरे में स्टेटस रिपोर्ट बनाकर देने का निर्देश दिया
- राज्य के तीन जिलों के तीन अस्पतालों से सामने आई है अब तक 60 मौतें

सार्वजनिक स्वास्थ्य मिलिंद म्हैसकर, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा दिनेश वाघमारे और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी और सभी कलेक्टर शामिल थे। शिंदे ने दोहराया कि नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर में मौत के मामलों की जांच के लिए एक राज्यस्तरीय समिति नियुक्त की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सीएम ने उपचारात्मक उपायों का उल्लेख करते हुए कहा कि कलेक्टरों को दवाएं खरीदने का अधिकार दिया गया है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दवाओं की खरीद में कोई देरी

न हो।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य प्रणाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर काम कर रहे हैं और इसे लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, अस्पतालों के अधीक्षकों और जिला सर्जनों से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक टीम के रूप में काम करें और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक धनराशि और अतिरिक्त उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। जनशक्ति की कमी के मामले में सरकार ने जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग का अधिकार दिया है, और ऐसे मामलों में देरी होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीएम ने कहा कि दवाओं की उपलब्धता के संबंध में एक राज्य स्तरीय डैशबोर्ड है, और कहा कि इसका उपयोग सभी अस्पतालों द्वारा तत्काल आवश्यक दवाओं या उपकरणों की खरीद के लिए प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। शिंदे के निर्देश तब आए, जब राज्य कांग्रेस के नेतृत्व में राज्यपाल रमेश बैस से मिले एक प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में हुई मौतों की जांच सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने, सभी मृतक पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की।

अजित दादा जल्द बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री,
NCP कोटे के मंत्री का बड़ा दावा

मुंबईः महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि अजित दादा जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे. नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मराव बाबा अत्राम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पांच साल बाद क्या होगा. लेकिन अजितदादा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. दरअसल, अत्राम का यह बयान राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के बयान के बाद आया है. बता दें कि फडणवीस ने कहा था कि अगर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो वे उन्हें पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे. इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा छिड़ गई है. फडणवीस के बयान का मतलब ये है कि अजित दादा अगले चुनाव के बाद या उससे पहले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे ताकि दादा मुख्यमंत्री बन सकें. राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता- अत्राम

अत्राम से जब ये पूछा गया कि क्या अजितदादा अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता.

'असली' NCP पर EC की सुनवाई से पहले शरद पवार बोले
'यदि चुनाव चिह्न बदल भी जाता है तो...'

मुंबईः 'असली' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर फैसला करने को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई होने वाली है. इसके पहले शरद पवार की अगुवाई वाले धड़े ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया. पवार ने चुनाव चिह्न 'घड़ी' की परवाह किए बिना अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया. शरद पवार (82) ने एनसीपी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उनके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया गया और 'कुछ उन निर्वाचित प्रतिनिधियों की हरकतों की कड़ी निंदा की गई जो पार्टी से अलग हो गए.' यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब एक दिन बाद चुनाव आयोग पार्टी के नाम और निशान पर शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के प्रतिद्वंद्वी धड़ों के दावों पर सुनवाई करने वाला

है. आज की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, ''पूरी पार्टी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में अटूट विश्वास जाहिर करती है और उनके मार्गदर्शन में देश में भावी चुनावों की तैयारी कर रही है.''

मैंने कई चिह्नों पर लड़ा चुनाव- शरद पवार

शरद पवार ने कहा, ''देश का मूड बदल रहा है. आम आदमी होशियार है.... यदि चुनाव चिह्न बदल भी जाता है तो भी लोग अपना इरादा आसानी से नहीं बदलते हैं.'' वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह 1967 में 'बैलों के जोड़े' निशान पर अपना पहला चुनाव लड़ा था. उन्होंने कहा कि तीन साल बाद वह 'चरखा' निशान पर चुनाव लड़े और जीत गए. पवार ने कहा कि उन्होंने 'गाय और बछड़ा', 'हाथ', और 'घड़ी' के चिह्नों पर चुनाव लड़ा है.

हमारा प्रस्ताव करारा जवाब है - पवार

शरद पवार ने कहा, ''हमारा प्रस्ताव उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो असली एनसीपी होने का दावा कर रहे हैं.'' सन 1969 में कांग्रेस में हुए विभाजन तथा कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (ओ) के बनने से अपनी पार्टी की वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए शरद पवार ने कहा कि मतदाताओं ने इंदिरा गांधी का खुले दिल से समर्थन किया, जिनके संगठन को बाद में असली कांग्रेस के रूप में स्वीकार किया गया.

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी परिवार गिरफ्तार, ATS ने की कार्रवाई

नवी मुंबईः महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी दंपति और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. नेरुल पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की एक टीम ने सोमवार रात को छापेमारी के दौरान नेरुल इलाके की एक चॉल में तीन लोगों को देखा और उन्हें पकड़ लिया. अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी व्यक्ति (43) और उसकी पत्नी (40) तथा उनके बेटे (25) के पास भारत में ठहरने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था. उन्होंने बताया कि नेरुल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों और विदेशी अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों के

खिलाफ मामला दर्ज किया है.

अगस्त के महीने में भी हुई थी ऐसी ही कार्रवाई

एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल (एएचटीसी) ने नेरुल में एक आवासीय इलाके में छापा मारा. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोफिस मंसूर शेख (61) और विजयालक्ष्मी दिनेशकुमार राम (45) को पकड़ लिया, जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां रह रहे थे. अधिकारी ने कहा कि दोनों के खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जो पिछले सात से आठ वर्षों से इलाके में रह रहे थे. इस बीच, ठाणे शहर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने पिछले सप्ताह भिवंडी शहर में एक 32 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था. कोनगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की एक टीम ने छापेमारी की और बांग्लादेश के चटग्राम के मूल निवासी नूर हुसैन अब्दुल सलाम शेख को पकड़ लिया.

संपादकीय / लेख

बचाव की तैयारी...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सिक्किम की तीस्ता नदी में मंगलवार रात को अचानक बाढ़ आने और सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर चिंतित करने वाली है। इस फ्लैश फ्लड के कारण जगह-जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कें तो टूटी ही हैं, सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। अभी स्वाभाविक ही सबसे ज्यादा ध्यान लापता सैनिकों की तलाश करने और यह सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा है कि जहां भी जरूरी हो जल्द से जल्द मदद उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस प्राकृतिक आपदा के चलते किसी के जान गंवाने की नौबत न आए। लेकिन इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का भी जायजा लेकर उन्हें जल्द से जल्द पुरानी स्थिति में लाना होगा। उत्तरी सिक्किम का यह इलाका भारत-नेपाल सीमा के करीब पड़ता है। हालांकि फ्लैश फ्लड का मूल कारण बादल फटना है, लेकिन कई वजहें रहीं जिनसे यह हादसा अधिकाधिक गंभीर रूप लेता गया। बादल फटने की यह घटना उत्तर सिक्किम के चुंगथाम इलाके में स्थित ल्होनक झील के ऊपर हुई। यह झील ल्होनक ग्लेशियर पर बनी है। बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव के चलते लेक की दीवारें टूट गईं और भारी मात्रा में मलबे के साथ पानी तीस्ता में आया, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया।

हालांकि बचाव और राहत कार्यों को लेकर सिक्किम सरकार के साथ पश्चिम बंगाल सरकार का तंत्र भी सक्रिय हो गया है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में गौर करने वाली एक बात यह भी है कि आपदा प्राकृतिक जरूर है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती। ल्होनक झील इस क्षेत्र की 14 उन ग्लेशियल लेक्स में शामिल है, जिन्हें पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है। ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों से पिघल रहे ल्होनक ग्लेशियर का पानी इसी झील में जमा हो रहा था, जिससे इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी साल मार्च महीने में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हिमालय के तमाम ग्लेशियर अलग-अलग दर से, लेकिन तेजी से पिघल रहे हैं और इस वजह से हिमालय की नदियां किसी भी समय बड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकती हैं। यह सही है कि ग्लोबल वॉर्मिंग वैश्विक मसला है और किसी एक देश की सरकार अकेले अपने बूते इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बड़े और संवेदनशील ग्लेशियरों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए संभावित हादसों से निपटने की तैयारी जरूर की जा सकती है। इन हादसों के दायरे में आने वाले इलाकों के लोगों को भी अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूक रखा जा सकता है। इन उपायों से हादसे भले न टलें लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मनपा स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए सपा ने लगाई शिक्षा मंत्री से गुहार...

40 से अधिक जर्जर इमारतों में चल रहे हैं मनपा स्कूल

मुस्तकीम खान

भिवंडी: समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में प्रदेश सचिव रियाज आजमी समेत अन्य पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भिवंडी के दर्जनों जर्जर मनपा स्कूलों की मरम्मत कराने और प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, मनपा संचलित स्कूलों में गिरते शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से मुलाकात कर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के साथ ही एक ज्ञापन दिया गया. मालूम हो कि भिवंडी शहर के दर्जनों प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में हैं. कुछ बंद हो चुके है तो कुछ को भविष्य में बंद करने की योजना है. जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी धोखा दायक मनपा स्कूलों की मरम्मत के लिए तुरंत फंड उपलब्ध कराने की मांग करते हुए रियाज आजमी और पूर्व नगरसेवक फराज बहाउद्दीन बाबा ने शिक्षा मंत्री

से कहा है कि भिवंडी निजामपुर में एक स्कूल पूरी तरह इमारत जर्जर घोषित कर उसे विगत दिनों पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और लगभग 1200 छात्रों को विभिन्न मनपा स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं, मनपा के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का ड्रॉपआउट अनुपात काफी अधिक है। जो चिंता का विषय है. रियाज आजमी ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को बताया कि शहर के लगभग 40 मनपा स्कूलों की हालत खराब है उसकी मरम्मत के लिए मनपा के पास फंड नहीं है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा हैं , उन्होंने निजामपुर जर्जर उर्दू प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का जिक्र करते हुए कहा कि मरम्मत की लागत सिर्फ दो करोड़ थी, लेकिन मनपा प्रशासन ने स्कूल की मरम्मत कराने के बजाय उसे बंद कर दिया जिस के चलते हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है.

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को मनपा स्कूलों की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि अधिकांश नगरपालिका स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है, स्वच्छ पानी, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मनपा स्कूलों के खराब स्थिति के चलते छात्रों की संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। मनपा प्रशासन पर फळए ऐक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसे पटरी पर लाने की सख्त जरूरत है क्योंकि भिवंडी में पावरलूम श्रमिकों की एक बड़ी आबादी है, वे भी मनपा स्कूलों की खराब स्थिति के चलते अपने बच्चों को मनपा के स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। और जिसके कारण बड़ी संख्या में शहर के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं. शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इन सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद अबू आसिम आजमी समेत प्रतिनिधिमंडल में शामिल रियाज आजमी से मनपा स्कूलों की मरम्मत समेत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हुए कहा कि बहुत जल्द भिवंडी का दौरा कर उसके सुधार के लिए फैसला लेंगे इस प्रतिनिधिमंडल में रियाज आजमी, पूर्व नगर सेवक फराज बहाउद्दीन बाबा, रियाज शेख, आलमगीर खान सहित अन्य लोग मौजूद थे.

लोकल ट्रेनों की सेवाएं आए दिन बाधित, बेहतर सेवा देने का रेल प्रशासन का दावा फेल !

मुंबई : मुंबई महानगर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की सेवाएं आए दिन बाधित हो रही है। कभी रेल पटरियों पर हादसे तो कभी ट्रेन ही डिरेल हो जा रही है। ऐसे में मुंबईकरों को बेहतर सेवा देने का रेल प्रशासन का दावा फेल होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में रेल सेवा प्रभावित होने की खबरे आई हैं। ताजा खबर बुधवार की है जब मुंबई सेंट्रल के पास ट्रेन डिरेल हो गई। हालांकि, इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवाल एक बार फिर उठा। सेंट्रल रेल हो या वेस्टर्न रेल, दोनों में मेंटीनेंस की लापरवाही के चलते यह समस्या आती है। इस बात की पुष्टि रेलवे विभाग की अंतरिम रिपोर्ट में भी की गई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के वर्ष २०२१-२२ की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की कुल दुर्घटनाओं में से ६० प्रतिशत दुर्घटनाएं रेलवे या रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से हुई हैं। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस और सिग्नलिंग की समस्या के चलते रेलवे अपनी पटरी से डिरेल हो जाती है। रेलवे सेफ्टी कमिशनर की रिपोर्ट में वर्ष २०२१ - २०२२ में कुल २२ दुर्घटनाएं हुई हैं जब कि वर्ष २०२१-२२ में ३५ दुर्घटनाएं हुईं। जिसमें से ६० प्रतिशत दुर्घटनाओं में रेलवे कर्मचारी और रेलवे की लापरवाही को कारण बताया गया। सूत्रों की मानें तो रेलवे सेफ्टी कमिशनर की तरफ से दुर्घटनाओं के बाद कई बार सुरक्षा सिफारिशें की गई, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। रेलवे एक्टिविस्ट समीर झावेरी की मानें तो बुलेट ट्रेन का काम सभी तरफ जोर-शोर से शुरू है।

अस्पताल की क्षमता 200 मरीजों की... भर्ती हैं 400 मरीज

मुंबई : नांदेड़ जिला अस्पताल में ३५ लोगों की मौत से उठे सवालों के बाद महाराष्ट्र के सभी जिलों के अस्पतालों की अवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जनता के स्वास्थ्य की समस्या को लेकर नांदेड़ के बाद अब नगर जिला अस्पताल की स्थिति भी सामने आई है। यहां आईसीयू में जगह नहीं और ऑक्सीजन बेड भी फुल हैं। डेंगू और मलेरिया से परेशान लगभग ४०० मरीज भर्ती हैं, जबकि यहां अस्पताल की क्षमता २०० मरीजों की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डेंगू सहित विभिन्न महामारी रोगों से त्रस्त है। एक माह में डेंगू के ३९ मरीज मिले हैं। इसलिए जिला अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन १,१०० से अधिक मरीजों की जांच हो रही है। जिला अस्पताल में न तो आईसीयू बेड उपलब्ध हैं और न ही ऑक्सीजन बेड, कहीं दवाएं नहीं हैं तो कहीं इलाज में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। यहां शहर के जिला अस्पताल में दवाओं का

पर्याप्त भंडार है, लेकिन सच यह भी है कि कर्मचारियों की कमी और बेड्स की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण यहां मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल है।

गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में १८ बेड्स हैं, लेकिन सभी बेड्स फुल हैं। नए मरीज के लिए जगह नहीं है। जिला अस्पताल में २०० बेड का ऑक्सीजन सिस्टम है। यदि आईसीयू में जगह नहीं है तो उन मरीजों को परिजनों की सहमति से ऑक्सीजन बेड पर रखा जाता है लेकिन ये २०० बेड भी फुल हो गए हैं। इसलिए नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सका।

भिवंडी बेघर निवारा केंद्र में व्यवस्थापक और केयर टेकर घर बैठे ले रहे वेतन...

उपचार से वंचित है कई लाभार्थी, दो महीने के भीतर तीन की मौत

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी में गरीब बेघर नागरिकों के लिए मनपा द्वारा चलाए जा रहे तीन बेघर निवारा केंद्र में बड़ी लापरवाही और व्यवस्थापक, केयर टेकर द्वारा घर बैठे वेतन लेने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। इन बेघर निवारा केंद्रों को दिल्ली की निजी संस्था सादिक मसीह मेडिकल सोशल सर्वेंट सोसायटी चला रही है जहा लाभार्थियों की देख रेक में घोर लापरवाही के कारण समय पर इलाज न कराने को लेकर दो महीने के भीतर तीन मौत होने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि भिवंडी शहर के उर्दू हिन्दी पत्रकार संघ ने एस टी स्टेंड स्थित शहरी सहारा बेघर निवारा केंद्र पर गरीब लाभार्थी के लिए फल वितरण का कार्यक्रम आयुजित किया था जहां

संघ के अध्यक्ष अब्दुल गनी खान से वहां की एक बूढ़ी महिला ने बताया की वे एक हफ्ता से बीमार है लेकिन उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है ।जिस पर खान ने वहां पर मौजूद व्यवस्थापक त्रिवेडी कमला शंकर से कहा की इनकी देखभाल के लिए संस्था ने किसे नियुक्त किया है तो पता चला की इस निवारा केंद्र में व्यवस्थापक के लिए राजेश मोरे और केयरटेकर के तौर पर रहमतुल्लाह अंसारी और भारती धनंजय ठाकरे काम कर रहें लेकिन दोनो 18 सितंबर से छुट्टी पर है और उनकी जगह कल्याण रोड की सिंध ताई बेघर निवारा केंद्र की व्यवस्थापक त्रिवेडी शंकर यहां केंद्र में लाभाथीर्यों की देखरेख के लिए रखा गया है। जहां दिलचस्प बात यह है की उक्त केंद्र में दोनो की छुट्टी पर होने के बावजूद रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर बराबर किए जा रहे हैं और घर बैठे दोनों पुरा वेतन प्राप्त कर रहें है। जिसके बाद गनी खान ने मनपा में बैठे अधिकारी पुनियार्थी को फोन कर सूचना दी । मनपा अधिकारी उक्त बेघर निवारा केंद्र का निरक्षण करने के बाद कहा की यह अत्यंत गंभीर विषय है और जल्द ही इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी अब तक कोई करवाही नहीं की गई ।गनी खान ने बताया की एक मृतक सहारा बेघर निवारा केंद्र की है जिनका नाम राय बाई गणपत कांसे 80 है और अब भी उक्त केंद्र में एक महिला गंगू बाई को उपचार की अधिक आवश्यकता के बाद भी अस्पताल में भर्ती नही कराया जा रहा है । खान ने मनपा प्रशासन से शहर में बेघर निवारा केंद्र चला रही सादिक मसीह मेडिकल सोशल सर्वेंट सोसायटी दिल्ली संस्था का ठेका तुरंत रद्द करने की मांग की है।

२ लाख 95 हजार रुपए की पानी चोरी... पुलिस में पानी चोरी का मामला दर्ज

मुस्तकीम खान

भिवंडी : शांतिनगर क्षेत्र अंतर्गत उमर कांप्लेक्स स्थित एक अवैध इमारत में जलापूर्ति विभाग की बगैर मंजूरी 15 नल कनेक्शन जोड़कर 2 लाख 95 हजार रुपए की पानी चोरी का मामला उजागर हुआ है। जलापूर्ति कनिष्ठ अभियंता ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में इमारत मलिक के खिलाफ चोरी का मामला दाखिल कराया है। जलापूर्ति अभियंता द्वारा पुलिस में की गई पानी चोरी शिकायत से शहर में पानी चोरी में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। जल आपूर्ति अभियंता संदीप पटनावर ने बताया है कि पानी चोरी वालों के खिलाफ उनकी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, शांतिनगर परिसर स्थित अवैध इमारत के मालिक हासिम अब्दुल वफा खान द्वारा जलापूर्ति विभाग से बगैर मंजूरी लिए ही 15 अनधिकृत नल कनेक्शन जोड़कर इमारत में रहने वाले रहिवासियों को दिया था. पानी चोरी का मामला संज्ञान में आते ही जलापूर्ति विभाग अभियंता संदीप पटनावर के आदेश पर जलापूर्ति कनिष्ठ अभियंता उद्धव गावडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर समुचित जांच पड़ताल कर अवैध रूप से जोड़े गए 15 नल कनेक्शन को काटकर अलग कर दिया और शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पानी चोरी में लिप्त हासिम अब्दुल वफा खान पर पानी चोरी किए जाने का आपराधिक मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच शांतिनगर पुलिस कर रही है।

HC ने नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लिया

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नांदेड़ के डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लिया, जहां 16 बच्चों सहित 35 मरीजों की मौत हो गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य के लिए अपने बजटीय आवंटन का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने बजटीय आवंटन के बारे में विवरण मांगा और राज्य को चेतावनी दी कि यदि मौतें जनशक्ति या दवाओं की कमी के कारण हुईं तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. की खंडपीठ ने उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने अधिवक्ता मोहित खन्ना द्वारा लिखे गए एक पत्र का संज्ञान लिया। ''महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच असाधारण घटनाएं हुईं... नांदेड़ में डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज में 16 शिशुओं सहित 31 मरीजों की मौत और 18 की मौत सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच), छत्रपति संभाजीनगर में 2 और 3 अक्टूबर के बीच मरीज, ''पत्र में कहा गया है। महाधिवक्ता बीरेंद्र सर्राफ अदालत में उपस्थित हुए और स्वेच्छा से जानकारी देने को कहा. इसके बाद अदालत ने स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन जानने के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता और रिक्ति के बारे में भी जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने इस मामले को गुरुवार को रखा. ''डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए बयानों सहित मीडिया रिपोर्टों में बेड, डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की कमी को मरीजों की मौत का प्राथमिक कारण बताया गया है...हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने घटनाओं के संबंध में जांच शुरू कर दी है, कोई भी ऐसा कर सकता है केवल उन नागरिकों की दुर्दशा की कल्पना करें जो स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए सरकार के साथ-साथ उन लोगों के रिश्तेदारों पर भी निर्भर हैं, जो बीहड़ के शिकार लोगों के रिश्तेदारों पर निर्भर हैं,'' वकील खन्ना ने एचसी को लिखे पत्र में लिखा है। नांदेड़ अस्पताल में 72 घंटों में 16 बच्चों सहित 31 मौतें दर्ज होने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। नांदेड़ में हुई मौतों के अलावा, श्री खन्ना के पत्र में छत्रपति संभाजीनगर के एक सरकारी अस्पताल में शिशुओं सहित 18 मौतों का भी उल्लेख किया गया है।

सीबीआई ने 21 करोड़ डिफॉल्ट मामले में लॉजिस्टिक्स फर्म, निदेशकों पर मामला दर्ज किया

मुंबईः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक को कथित तौर पर 21.48 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी और उसके प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है।

आईडीबीआई बैंक के जीएम ने दर्ज करायी शिकायत

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, 9 सितंबर, 2023 को आईडीबीआई बैंक, मुंबई की महाप्रबंधक शिप्रा तिवारी से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी, जिसका कार्यालय भोपाल में है, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य लोगों ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आईडीबीआई बैंक को धोखा देने की साजिश और उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आरोपी ने धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन, धन का विचलन, संबंधित / सहयोगी कंपनियों के बीच परिपत्र लेनदेन, आय और व्यय की पुस्तकों की गलत बयानी करके स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने कथित तौर पर 2010-16 के दौरान आईडीबीआई बैंक को कुल 21.48 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को लाभ पहुंचाया।

''इसके अलावा शिकायतकर्ता बैंक ने शिकायत में उक्त धोखाधड़ी में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों की भूमिका, संलिप्तता की जांच करने का अनुरोध किया है। फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फोरेंसिक ऑडिट 1 नवंबर, 2010 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए किया गया था। फोरेंसिक ऑडिटर के निष्कर्षों के मद्देनजर, कंपनी के खाते को 25 अक्टूबर, 2022 को आईडीबीआई बैंक द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया था और इसकी सूचना दी गई थी। आरबीआई 29 अक्टूबर, 2022 को, ''एक अधिकारी ने कहा।

दादर के एक होटल व्यवसायी को मिली जान से मारने की धमकी... कॉलर ने मांगा 1 करोड़

मुंबईः दादर के एक होटल व्यवसायी को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर -1 करोड़ की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। शिवाजी पार्क पुलिस के अनुसार, जहां मामला दर्ज किया गया था, 41 वर्षीय शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ शिवाजी पार्क इलाके में रहता है। 8 सितंबर को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने

रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अज्ञात फोन करने वाले के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज कर लिया है. ''क्या तुम बहुत होशियार हो गये हो? होशियार मत बनो, तुमने मुझे -1 करोड़ नहीं दिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा,'' फोन करने वाले ने शिकायतकर्ता से कहा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच चल रही है और शुरूआती जांच में पता चला कि आरोपी ने जासूसी तकनीक का इस्तेमाल कर पैसे ऐंठने की कोशिश की थी.

साइबर स्कैमर्स ने तीन को दिया चूना, कैसे किया अपराध

ठाणेः ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसकर साइबर बदमाशों ने तीन अलग-अलग मामलों में ठाणे के तीन लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है और धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपये है। इनमें से एक व्यक्ति से 77 लाख 91 हजार की ठगी की गई है और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है. हालाँकि, पुलिस प्रशासन साइबर अपराध को रोकने में विफल रही है और नागरिक यह सवाल उठाने लगे हैं कि इस अपराध पर कब काबू पाया जाएगा. चेतन (बदला हुआ नाम) कलवा इलाके में रहता है और एक निजी कंपनी में काम करता है। उन्हें एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि यदि वे ऑनलाइन कार्य पूरा करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कार्य पूरा किया। इस काम के लिए चेतन को कुछ

पैसे मिले. बाद में साइबर अपराधियों ने उनसे पैसे की मांग की और बिटकॉइन खरीदने को कहा. उन्होंने तदनुसार कार्य किया। लेकिन समय-समय पर घोटालेबाज मुनाफा कमाने का दावा कर बिटकॉइन खरीदने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठने लगे। लेकिन, अचानक भामटों ने आपसे नुकसान की भरपाई के लिए तीन लाख की मांग कर दी। जब भमटा ने चेतन से इस तरह लाखों रुपए ऐंठ लिए तो उन्होंने यह रकम निकालने की कोशिश की। लेकिन, पैसा नहीं मिला. इस बारे में पूछने पर भामता ने आपके अंक 90 बताए हैं। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपये देने होंगे. 20 लाख रुपए देने के बाद भामटाओं ने टैक्स के नाम पर उनसे 13 लाख रुपए ले लिए। बाद में दो किश्तों में 23 लाख रुपए देने के बाद भामटाओं ने उससे 10 लाख रुपए की मांग की। उस वक्त चेतन को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है. कुल 77 लाख 91 हजार रुपये की धोखाधड़ी के कारण चेतन की शिकायत के बाद कालवा पुलिस स्टेशन में भामटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कलवा के एक अन्य व्यक्ति से 24 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई और इस व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसे कमाने का संदेश भेजा गया। बाद में उनके बैंक खाते में कुछ रकम भेज दी गयी. साथ ही, उनका विश्वास हासिल करने के बाद भामटों ने उनसे लाखों रुपये भी वसूले और इस मामले में कलवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ठाणे के घोड़बंदर इलाके में रहने वाले एक शख्स से भी भामटों ने 35 लाख 84 हजार की ऑनलाइन ठगी की है. इस मामले में कासरवडवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और इन तीनों मामलों में धोखाधड़ी का आंकड़ा करीब 1 करोड़ 37 लाख है.

खेतों में उगाई गई 10 क्विंटल से अधिक भांग जब्त!

4 व्यक्तियों पर मामला दर्ज...

महाराष्ट्रः अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि पर भांग की खेती का पता लगाया है और लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की 10 क्विंटल से अधिक तस्करी जब्त की है। उन्होंने बताया कि भांग के पौधे महागांव तालुका के घोंसरा और बरगवाड़ी गांवों में 20 एकड़ में फैले छह अलग-अलग खेतों में कपास और अरहर की फसलों के बीच उगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक पवन बंसोड़ ने कहा कि लगभग 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये मूल्य की लगभग 10 से 12 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

गैर इरादतन हत्या के आरोप में नांदेड़ सरकारी अस्पताल के डीन... डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर

महाराष्ट्र : एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक डीन और एक डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है, जहां 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कार्यवाहक डीन एसआर वाकोडे और एक प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी और उसके नवजात बच्चे की मौत के संबंध में शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 30 सितंबर के बाद से 48 घंटों में अस्पताल में शिशुओं सहित कम से कम 31 मौतें दर्ज की गईं। अधिकारियों के अनुसार, 2 से 3 अक्टूबर तक अस्पताल में छह और मौतें दर्ज की गईं। एफआईआर के मुताबिक, 21 साल की गर्भवती महिला अंजलि को 30 सितंबर की रात करीब 8 बजे अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने 1 अक्टूबर को लगभग 1 बजे एक बच्ची को जन्म दिया। अंजलि के पिता कामाजी टोम्पे ने शिकायत में कहा कि बाद में डॉक्टरों ने कहा कि मां और बच्ची ठीक हैं। बाद में सुबह अंजलि को रक्तस्राव होने लगा और बच्चा भी ठीक नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने परिवार के सदस्यों को दवाएँ, ब्लड बैग और अन्य आवश्यक सामान बाहर से लाने के लिए कहा। टोम्पे ने दावा किया कि जब सामान लाया गया, तो डॉक्टर वार्ड में मौजूद नहीं थे। उन्होंने शिकायत में आगे दावा किया कि वाकोडे ने जानबूझकर उन्हें बैठाया और अंजलि की जांच के लिए डॉक्टर या स्टाफ नर्स नहीं भेजा।

शिकायत में कहा गया, ''डॉक्टरों ने अंजलि के बच्चे को मृत घोषित कर दिया और 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शव हमें सौंप दिया। बाद में, 4 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे अंजलि को मृत घोषित कर दिया गया।'' टोम्पे ने आरोप लगाया कि डीन ने जानबूझकर डॉक्टरों को अंजलि का इलाज नहीं करने दिया. उन्होंने शिकायत में कहा कि डॉक्टरों ने परिवार के सदस्यों को 45,000 रुपये की दवाएं बाहर से लाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों, नर्सों और दवाओं की उपलब्धता की कमी के कारण उनके सामने कई मरीजों की मौत हो गई. इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए वाकोडे से संपर्क नहीं हो सका। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों को बहुत गंभीरता से लिया है और विस्तृत जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, जबकि उन्होंने दवाओं और कर्मचारियों की कमी से इनकार किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर शहरों में दो सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि डॉक्टरों द्वारा बिस्तरों, कर्मचारियों और आवश्यक दवाओं की कमी का हवाला देते हुए दिए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लऊ ने महाराष्ट्र सरकार से भी विवरण मांगा।

अपने खिलाफ आपराधिक मामला निपटाने के बहाने एक व्यक्ति से 1.95 करोड़ की ठगी

मुंबईः माटुंगा स्थित एक व्यवसायी ने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया है कि चार लोगों ने उससे 1.95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले के मुख्य आरोपी, अली रजा शेख और पीड़ित एरिक जिमी अंकलेसरिया, 43, दिसंबर 2020 में एक-दूसरे से मिले, जब वे दोनों खारघर के एक केंद्र में संगरोध में थे। एरिक को पहले अपने निजी क्षेत्र में नर्सों की समस्या वाले मरीज के रूप में पेश करके कई महिला फिजियोथेरेपिस्टों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीओवीआईडी-19 प्रोटोकॉल के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद, अदालती सुनवाई से पहले उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया था।

जालसाज ने एरिक को कैसे ठगा?

एरिक के मुताबिक, शेख ने नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में टमाटर के आयात-निर्यात का बड़ा कारोबार होने का दावा किया था। उन्होंने एक प्रभावशाली व्यक्ति होने का भी दावा किया और एरिक को उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों से छुटकारा पाने में मदद का आश्वासन दिया। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किये. सितंबर 2021 में, एरिक को शेख का फोन आया, जहां शेख ने अपने 'दोस्त' जय उर्फ राजू मंगलानी का जिक्र किया, जिसके मंत्रालय और उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। शेख ने एरिक को मिलने के लिए नवी मुंबई के होटल तुंगा में बुलाया। शेख ने एक अन्य व्यक्ति वाल्मिक गुलमोहर का परिचय कराया, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी था। पीड़ित को मामला रद्द करने के लिए 37 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया और एरिक ने पैसे का भुगतान किया। बाद में, शेख ने एरिक को विधान भवन आने के लिए कहा, जहां उसकी मुलाकात 'चव्हाण' नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे मदद करने का आश्वासन दिया और बदले में 47 लाख रुपये मांगे। अक्टूबर 2021 में, शेख ने उसे विजय नादर और उसके दोस्त विक्रांत सोनावणे से मिलवाया क्योंकि एरिक शराब का लाइसेंस चाहता था। उन्होंने 30.50 लाख रुपये का सौदा किया और शेख को 15 लाख रुपये की टोकन राशि मिलेगी। कुछ दिनों के बाद, शेख ने लाइसेंस के लिए अतिरिक्त 6.43 लाख रुपये की मांग की।

फरवरी 2022 में जब एरिक ने उनसे सारे पैसे वापस देने के लिए कहा क्योंकि वादे के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ था, तो शेख ने कथित तौर पर उसे दादर में पारसी कॉलोनी के पास आने के लिए कहा, जहां उसने उस पर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि 'पैसे न मांगें' और अगर वह एरिक ने पुलिस को बताया, ''ऐसा किया, तो उसे मार दिया जाएगा।'' एरिक का दावा है कि शेख और उसके सहयोगियों को कुल 1,95,68,000 रुपये प्रदान किए गए थे। माटुंगा पुलिस ने पांच आरोपियों, मुख्य रूप से शेख, के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com